क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अक्तूबर, 1992 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्कीम फार रूरल एस० एस० आई०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण और पिछले क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) : (क) से (ग) ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के लघु उद्योगों के लिए एक एकीकृत बुनियादी सुविधा विकास योजना (तकनीकी की सहायता सहित) का मसौदा तैयार किया गया है और लघु, अति लघु तथा ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने व सुदृढ़ करने के लिए 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीतिगत उपायों का अनुपालन करते हुए इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) के प्रस्तावों में शामिल किया गया है। योजना के मसौदे को केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों में संबंधित प्राधिकरणों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

औद्योगिक विकास दर में कमी

1723. श्रीमती सुषमा स्वराज :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों में औद्योगिक उत्पादन की दर 3.5 प्रतिशत रही है।

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए औद्योगिक विकास की वार्षिक दर इससे ऊंची नियत की गई है,

(ग) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह लक्ष्य प्राप्त हो पाने की संभावना है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के औद्योगिक उत्पादन के विकास की वार्षिक दर कितनी हो पाने का अनुमान है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार नवीनतम उपलब्ध अवधि अर्थात् जुलाई, 1992 के लिए औद्योगिक उत्पादन की विकास दर एक वर्ष पहले की इसी अवधि की तुलना में (+) 2.1 प्रतिशत अधिक थी।

(ख) आठवीं योजना (1992–97) के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के लिए 8.4 प्रतिशत विकास दर निश्चित की गई है।

(ग) और (घ) सरकार वार्षिक आधार पर औद्योगिक विकास दर के लक्ष्य निश्चित नहीं करती है। जुलाई, 1991 में औद्योगिक नीति में घोषित नीति संबंधी प्रयासों, निर्यात और आयात नीति, 1992–97 में किए गए परिवर्तनों तथा इसके पश्चात् केन्द्रीय बजट, 1992–93 में किए गए प्रयासों और चालू वित्त वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में और सुधार होने की आशा है।